श्री चतुरानन मिश्र : आप सब बात कह दीजिए। उसके बाद आपको जवाब दे देंगे। यह बार-बार उठना, बैठना समझ में नहीं आता। . . .(**व्यवधान**). . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि समिति बन जाती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट की इंपलीमेंटेशन की बात है।

SHRI SOM PAL: The action should have been taken at the time of the harvest. If you take action now, it is not going to be of any use. It is infructuous. I am walking out in protest.

(The hon. Member then left the Chamber.)

श्री चतुरानन मिश्र : देखिए, हमारे पास रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। यही रिपोर्ट आई थी कि हम यह करेंगे तो हमने कॉमर्स मिनिस्टरी को लिखा था कि इनको इजाजत दे दी जाए एक्सपोर्ट करने की। कॉमर्स से आया था कि 13 लाख बेल का हम लोग देंगे, यही काटन के लिए।

Re. Scarcity of drinking water in Uttarakhand area of U.P.

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, जिसे अब उत्तरांचल और उत्तराखंड के नाम से जाना जा रहा है, वहां पेयजल के संकट के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उस क्षेत्र का यह दुर्भाग्य कहना चाहिए कि वहां का जो मीठा जल है वह बड़ी मात्रा में प्रवाहित होकर मैदान में आता है, लेकिन वहां पेयजल की समस्या बनी हुई है। यानि जैसी कहावत है— पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उसके उपयोग में नहीं आ रही है। उस क्षेत्र में अनेक बड़ी पेयजल योजनाएं बनीं, जैसे पिथौरा गढ़ की जलापूर्ति योजना है, अल्मोड़ा की जलापूर्ति योजना है, पौड़ी की जलापूर्ति योजना है। यह तो नगरीय क्षेत्र हैं, यहां के जिला मुख्यालय भी हैं। इसके अलावा दूसरी योजना है हिंडोलारवाल योजना, दशरथ पंपिंग योजना, कोट पम्पिंग योजना, अनेक ऐसी योजनाएं हैं, जो पचास-पचास, साठ-साठ ग्रामीण समूह के लिए बनी हुई हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विशाल पूंजी जल की आपूर्ति के लिए उस क्षेत्र में लगाई जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है इस बार भी इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र ने 10 करोड़ रुपए अलग से उस क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के लिए गढ़वाल मंडल को दिए हैं और 30 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने मुहैया कराया है। लेकिन स्थिति यह बन गई है कि वहां पर चारों तरफ पेयजल की हा-हाकार हो रही है और प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती। दुर्भाग्य यह है कि वहां का जो शासन तंत्र है उसको इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती है कि वह पानी की व्यवस्था कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है और यह होता है कि मैदान की तरह जो इंडिया मार्क के हैंड पम्प यहां पर लगाए गए हैं, पहाड़ में खार कहते हैं, जिसको शिखर कह सकते हैं, उस शिखर के स्थान पर भी इंडिया मार्क के हैंड पम्प लगे हुए हैं, यह इस बात का प्रतीक है कि वहां का प्रशासन उस दिशा में अचेतन है और यही कारण है कि पूरे क्षेत्र में हा-हाकर मच गया है, सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करती है तो प्रशासन यह करता है कि जब पानी घट जाता है तो नगरीय क्षेत्रों में टैंकरों से पानी दिया जाता है लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसकी चिंता नहीं की जाती है और दिखाने के लिए लगभग जून के बाद कहीं-कहीं खच्चरों से पानी भेजा जाता है। आप सब अनुभव कर सकते हैं कि खच्चरों से पेयजल की कैसी आपूर्ति होगी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो जल का संकट है, यह एक प्रकार का कृत्रिम संकट है और इसके लिए शासन में बैठे हुए लोग बड़ी मात्रा में जिम्मेदार है क्योंकि जो फंड दिया जाता है वह बड़ी मात्रा में दूसरे रास्तों से दूसरी तरफ चला जाता है और उससे कोई परिणाम नहीं आता है। मैं यह भी चाहता हूं कि ठीक समय पर, जैसे अभी पानी की कमी शुरू हो रही है। उसकी व्यवस्था शासन अभी से कराए और उसकी मॉनिटरिंग, देख-रेख की व्यवस्था भी कराए।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

Re. Enactment of Legislation for Agricultural Workers

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): महोदय, फिर एक बार मैं सरकार की उस प्रतिबद्धता की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो खेत मजदूरों के बारे में केन्द्रीय कानून बनाने के बारे में है।

महोदय, इस बारे में बहुत बार यहां बहस हो चुकी है और सरकार की तरफ से श्रम मंत्री ने दो-दो बार इस सदन में अपने कमिट्मेंट को दोहराया कि शीघ्र ही यह कानून बनाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट इस बारे में